MA 3rd semester (CBCS)

Paper (iv)th sociology of environment (Course Code: SOC 304)

Unit (iii). Action plan for climate change

Reading material by . Dr. Sangeeta Pandey
professor, sociology Department

D.D.U. Gorakhpur University

Email - sangeeta.pandey1989@gmail.com

- **क्लाइमेट चेंज की वैश्विक समस्या से बचाव हेतु यूनाइटेड नेशनस द्वारा निर्देशित CO2 के कम उत्सर्जन हेतु एवं हरित प्रयासों के संदर्भ में भारत द्वारा किया गया यह समेकित प्रयास है जो 2008 में Action plan of India(एक्शन प्लान ऑफ इंडिया) के रूप में सामने आया ।**

भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भारत सरकार जून 2008

30 जून 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत का पहला जलवायु (NAPCC) परिवर्तन, वर्तमान और भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों को जलवायु समन और अनुकूलन के समाधान की रूपरेखा पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की । योजना के 8 मुख्य मिशन 2017 को लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं । प्रधानमंत्री के परिषद द्वारा यह विस्तृत कार्य योजना दिसंबर 2008 में मंत्रालयों को सौंप दी गई इस जलवायु परिवर्तन की योजना में उच्च आर्थिक विकास दर को बनाए रखने तथा जीवन स्तर को बढ़ाने की सर्वोपरि प्राथमिकता पर बल दिया गया है।

1. **राष्ट्रीय सौर मिशन – NAPCC** शक्ति और जीवाश्म आधारित ऊर्जा (गैर परंपरागत स्रोत) विकल्पों के साथ सौर प्रतिस्पर्धी बनाने के परम उद्देश्य के साथ 2017 तक किया

गया आने वाली पीढ़ी के अन्य उपयोगों के लिए विकास और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य इस योजना में शामिल हैं ।

- शहरी क्षेत्रों उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सौर तापीय प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के लिए विशिष्ट लक्ष्य हैं ।
- 1000 मेगावाट/वर्ष का photovaltaics उत्पादन में वृद्धि का एक लक्ष्य है ।
- सौर तापीय विद्युत उत्पादन के कम से कम 1000 मेगावाट की उपलब्धता का लक्ष्य है ।

2. संबंधित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन –

वर्तमान पहल करने के लिए 2012 तक 10,000 मेगावाट की बचत की उम्मीद की जा रही हैं तथा बिल्डिंग ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की भी योजना की सिफारिश की गई है ।

- ऊर्जा की खपत कम करने के लिए **'विशिष्ट ऊर्जा खपत'** को अनिवार्य किया गया है तथा व्यापार कंपनियों के लिए ऊर्जा बचत के उद्देश्य से ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र की व्यवस्था लागू की गई है ।
- **'ऊर्जा कुशल उपकरणों'** के द्वारा कम ऊर्जा खर्च को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।
- नगरपालिकाओं द्वारा इमारतों में ऊर्जा की मांग के पक्ष का प्रबंधन करना एवं कृषि क्षेत्रों में भी ऊर्जा की खपत कम करने से संबंधित प्रयास करना तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की भागीदारी हेतु वित्त की व्यवस्था करना ।

3. सतत् पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन –

नियोजन के एक प्रमुख घटक के रूप में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने से संबंधित है ।

- वर्तमान में **'ऊर्जा संरक्षण निर्माण कोड'** का विस्तार करना ।
- शहरी अपशिष्ट प्रबंधन और रीसाइकलिंग करके कचरे से बिजली उत्पादन आदि पर अत्यधिक जोर देना ।
- आटोमोटिव ईंधन अर्थव्यवस्था के मानकों के प्रवर्तन को मजबूत बनाना और मूल्य निर्धारण का उपयोग कर कुशल वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के उपाय करना ।

- सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को प्रोत्साहन देना ।

4. राष्ट्रीय जल मिशन –

पानी की कमी को दूर करने हेतु खराब जल को शुद्ध करना, जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान ढूंढना और योजना मूल्य निर्धारण और अन्य उपायों के माध्यम से जल उपयोग की दक्षता में 20% सुधार का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

5. हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन –

हिमालय क्षेत्र में , जहां की ग्लेशियर भारत के पानी की आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत हैं , वहां अब ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम के रूप में ये ग्लेशियर दूर होते जा रहे हैं अर्थात पिघलते जा रहे हैं । इस योजना में इन ग्लेशियरों का संरक्षण करने का उद्देश्य है , तथा इस क्षेत्र में जैव विविधता , वन और अन्य पारिस्थितिकी मूल्यों का संरक्षण करने का उद्देश्य निर्धारित है ।

6. एक ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन –

इसमें अवक्रमित वन भूमि का सुधार करने , भारत के वनों का विस्तार करने के उद्देश्य से 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वनीकरण करने तथा राज्य क्षेत्र के 23% से 33% क्षेत्रों को वनों से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

7. संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन –

इस योजना का लक्ष्य जलवायु आधारित फसलों के लिए **'मौसम बीमा तंत्र'** का विस्तार करना और कृषि पद्धतियों के विकास के माध्यम से कृषि में जलवायु अनुकूलन का समर्थन करना है ।

8. जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन –

इस योजना में जलवायु विज्ञान के ज्ञान का विकास करना , जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और चुनौतियों की उचित जानकारी करना , एक नई जलवायु रिसर्च फंड की व्यवस्था करना , जलवायु सुधार के मॉडल (प्रारूप) पर विचार करना और इन सबके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना सम्मिलित है । इसके साथ ही निजी क्षेत्र के पहल से **'उद्यम पूंजी कोष'** के द्वारा अनुकूलन और शमन (निस्तारण से संबंधित) प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का प्रोत्साहन भी शामिल है ।

उपर्युक्त प्रत्येक मिशन के लिए नेतृत्व की जिम्मेदारी मंत्रालयों को दी गई है , जो इसके उद्देश्यों , रणनीतियों के कार्यान्वयन , समय - सीमा और निगरानी तथा मूल्यांकन के मानदंडों का विकास व जलवायु परिवर्तन मिशन पर कार्य करेगा । प्रधानमंत्री की परिषद भी समय-समय पर समीक्षा करने और मिशन की प्रगति पर रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होगी ।